नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 169
दि. 24.03.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल का डीकिन यूनिवर्सिटी-गिफ्ट सिटी कैंपस की प्रथम स्नातक बैच के दीक्षांत समारोह में प्रेरक संबोधन

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के एजुकेशन सेक्टर का ग्लोबल नीड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

- गुजरात ट्रेड तथा ट्रेडिशन से आगे बढ़कर ग्लोबल इकोनॉमिक और नॉलेज सेंटर के रूप में उभर रहा है
- भारत ने पिछले एक दशक से ग्लोबल नॉलेज और एजुकेशन सेक्टर के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में लगातार वृद्धि हुई है
- इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और स्किल आधारित कोर्स के माध्यम से शिक्षा को उद्योग से जोड़कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया गया है
- गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और शिक्षा का अनूठा समन्वय हुआ है
- निफ्ट, एनआईडी, आईआईटी-गांधीनगर, डीए-आईआईसीटी, नाइपर जैसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं के कारण गांधीनगर अब एजुकेशनल हब बन गया है.

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश के एजुकेशन सेक्टर का ग्लोबल नीड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। इसके लिए उन्होंने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्रीवन एजुकेशन पर जो जोर दिया है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को ऑस्ट्रेलियाई डीकिन यूनिवर्सिटी के गिफ्ट सिटी कैंपस की प्रथम स्नातक बैच के दीक्षांत समारोह में प्रेरक संबोधन दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने डिग्री प्राप्त कर रहे युवाओं और डीकिन यूनिवर्सिटी को बधाई देते हुए कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय शाखा कैंपस के रूप में डीकिन यूनिवर्सिटी ने जो शुरुआत की है उसके गिफ्ट सिटी कैंपस की पहली बैच का दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्रदान करने का अवसर नहीं है, बल्कि भारत के ग्लोबल नॉलेज सेंटर के रूप में हुए परिवर्तन को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर है। उन्होंने यह भी कहा कि यह दीक्षांत समारोह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ती साझेदारी का प्रतिबिंब भी है।

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना के साथ विश्व कल्याण का मार्ग दिखाया है और उनके मार्गदर्शन में गुजरात ट्रेड और ट्रेडिशन से आगे बढ़कर ग्लोबल इकोनॉमिक और नॉलेज सेंटर के रूप में उभर रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री काल से ही गुजरात ने शिक्षा क्षेत्र में अनेक नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। उन्होंने अपने विशिष्ट विजन के तहत दुनिया की श्रेष्ठ सुविधाएं गुजरात के युवाओं और विद्यार्थियों को उनके घर के पास ही उपलब्ध कराने का दृष्टिकोण अपनाया। इसके परिणामस्वरूप राज्य में फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, मेरिटाइम यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी तथा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जैसी सेक्टर-स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्थापित हुई हैं।

उन्होंने आगे कहा कि गिफ्ट सिटी भी प्रधानमंत्री के विशिष्ट विजन का एक जीवंत उदाहरण है। इसलिए गिफ्ट सिटी में फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और शिक्षा का अनूठा समन्वय हुआ है तथा यहां चार फॉरेन यूनिवर्सिटी भी कार्यरत हैं।

मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है। 2014 में आईआईटी की संख्या 16 थी, जो बढ़कर आज 23 हो गई है और इनके वैश्विक कैंपस भी शुरू हुए हैं। आईआईएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है और एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 20 हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन में लगातार सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और स्किल आधारित पाठ्यक्रमों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' और 'स्टार्टअप इंडिया' के साथ समन्वय कर शिक्षा को उद्योग से जोड़ते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की विजनरी लीडरशिप में भारत ने पिछले एक दशक में ग्लोबल नॉलेज और एजुकेशन सेक्टर में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं, जिसका साक्षी यह समारोह है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 'स्वयं' और 'दीक्षा' जैसे ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लर्निंग इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया है, साथ ही फॉरेन यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हुए रिसर्च, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट पर विशेष जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने विशिष्ट विजन के साथ 'स्टडी इन इंडिया' और 'ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स (ज्ञान)' जैसे योजनाओं से भारत को वर्ल्ड एजुकेशन हब बनाने के लिए मजबूत आधार तैयार किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज भारत की प्रतिभा और संभावनाओं पर दुनिया का विश्वास स्पष्ट रूप से बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन तथा नेतृत्व में तैयार हुई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा शिक्षा को वैश्विक मानकों से जोड़ा गया है।

उन्होंने गौरवपूर्वक कहा कि निफ्ट, एनआईडी, आईआईटी-गांधीनगर, डीए-आईआईसीटी, नाइपर जैसी प्रतिष्ठित संस्थाएं कार्यरत है; जिसके परिणामस्वरुप गांधीनगर एजुकेशनल हब बन गया है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर रहे युवाओं से अनुरोध किया कि वे अपने अध्ययन के दौरान अर्जित ज्ञान, कौशल और वैश्विक अनुभव का उपयोग करते हुए भविष्य में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आगे बढ़ें।

तमिलनाडु में सियासी समीकरण तय, एनडीए ने सीट बंटवारे के साथ चुनावी शंखनाद किया

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में चुनावी सरगर्मी अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने लंबे मंथन के बाद सीटों का बंटवारा तय कर चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति स्पष्ट कर दी है। इस समझौते के साथ ही राज्य में सत्ता की लड़ाई के लिए सियासी बिसात पूरी तरह बिछ चुकी है और सभी दल अपने-अपने समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं।

गठबंधन के तहत कुल 234 विधानसभा सीटों में से सबसे बड़ा हिस्सा AIADMK को मिला है, जो 178 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राज्य में एनडीए का नेतृत्व कर रही यह पार्टी अपने परंपरागत वोट बैंक और संगठनात्मक मजबूती के दम पर सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए हुए है। वहीं Bharatiya Janata Party 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी, जो पिछले चुनावों की तुलना में एक संतुलित लेकिन रणनीतिक हिस्सेदारी मानी जा रही है।

इसके अलावा Pattali Makkal Katchi को 18 सीटें और Amma Makkal Munnetra Kazhagam को 11 सीटें दी गई हैं। इस तरह एनडीए ने अपने सहयोगी दलों के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है, ताकि विभिन्न सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधा जा सके।

इस सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा एडप्पडी के. पलानीस्वामी ने चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, भाजपा के तमिलनाडु अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, पीएमके के प्रमुख अंबुमणि रामदास और एएमएमके के महासचिव टीटीवी दिनाकरन समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। यह संयुक्त उपस्थिति इस बात का संकेत भी थी कि गठबंधन के भीतर फिलहाल एकजुटता का संदेश देने की पूरी कोशिश की जा रही है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सीट बंटवारा केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। एआईएडीएमके को अधिक सीटें देकर गठबंधन ने पारंपरिक द्रविड़ राजनीति के आधार को मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि भाजपा और अन्य सहयोगी दलों को सीमित लेकिन प्रभावशाली सीटें देकर उनके वोट बैंक को जोड़ने का प्रयास किया गया है।

इस बीच, चुनावी माहौल में एक नया विवाद भी सामने आया है। कांग्रेस ने Election Commission of India से केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने अपने हलफनामे में बेंगलुरु के कोरमंगला इलाके में स्थित करीब 49,000 वर्गफुट के एक महंगे बंगले की जानकारी छिपाई है, जिसकी कीमत लगभग 200 करोड़ रुपये बताई जा रही है। इस आरोप ने चुनावी बहस को और तीखा कर दिया है और पारदर्शिता के मुद्दे को केंद्र में ला खड़ा किया है।

इसी दौरान छोटे दल भी अपनी भूमिका को मजबूत करने की कोशिश में हैं। ए.सी. षणमुगम, जो पुथिया नीधि काची के संस्थापक हैं, उन्होंने भाजपा के चुनाव चिह्न 'कमल' पर नौ सीटों से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने अपने पिछले चुनावी प्रदर्शन का हवाला देते हुए बताया कि 2014 में भाजपा के प्रतीक पर उन्हें 3.25 लाख वोट मिले थे, जबकि एआईएडीएमके के समर्थन से चुनाव लड़ने पर यह आंकड़ा बढ़कर 4.70 लाख तक पहुंच गया था।

यह पूरा घटनाक्रम इस बात का संकेत है कि तमिलनाडु में इस बार चुनाव केवल दो या तीन बड़े दलों के बीच नहीं, बल्कि गठबंधनों और उप-गठबंधनों के बीच होगा।

पीएमके में सियासी संग्राम गहराया, 'आम' चुनाव चिह्न पर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल कोर्ट का रास्ता दिखाया

नई दिल्ली/चेन्नई। तमिलनाडु की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली Pattali Makkal Katchi (पीएमके) इन दिनों आंतरिक कलह के दौर से गुजर रही है, जहां पिता-पुत्र के बीच छिड़ी वर्चस्व की लड़ाई अब अदालतों तक पहुंच चुकी है। इस बहुचिंत विवाद में सोमवार को Supreme Court of India ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि पार्टी के चुनाव चिह्न 'आम' पर मालिकाना हक का निर्णय चुनाव आयोग नहीं, बल्कि सिविल कोर्ट ही करेगा।

शीर्ष अदालत ने Madras High Court के पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने यह भी साफ किया कि चूंकि यह एक गैर-पंजीकृत राजनीतिक दल के भीतर का आंतरिक विवाद है, इसलिए Election Commission of India के पास इसमें दखल देने का अधिकार नहीं बनता।

यह विवाद मूल रूप से पीएमके के संस्थापक एस. रामदास और उनके बेटे अंबुमणि रामदास के बीच नेतृत्व और अधिकार को लेकर चल रही खींचतान से जुड़ा है। पिछले कुछ समय से दोनों के बीच मतभेद खुलकर सामने आए हैं और पार्टी के भीतर दो अलग-अलग गुट बन गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि रामदास ने अपने ही बेटे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद यह टकराव और तेज हो गया।

मामले की जड़ में 'आम' चुनाव चिह्न का स्वामित्व है, जो पार्टी की पहचान और राजनीतिक अस्तित्व का प्रतीक माना जाता है। रामदास गुट चाहता है कि यह चिह्न उनके नियंत्रण में रहे या फिर इसे पूरी तरह फ्रीज कर दिया जाए, ताकि विरोधी गुट इसका इस्तेमाल न कर सके। दूसरी ओर, अंबुमणि रामदास का गुट भी इस पर अपना अधिकार जताता रहा है, जिससे विवाद और उलझता गया।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे, ने अपने फैसले में कहा कि यह एक निजी अधिकार और स्वामित्व का मामला है, जिसे सिविल कानून के तहत ही सुलझाया जाना चाहिए। अदालत ने टिप्पणी की कि हाई कोर्ट के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है और उसे यथावत रखा जाता है।

हालांकि, अदालत ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह भी निर्देश दिया कि सिविल कोर्ट इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करे, ताकि चुनाव से पहले स्थिति स्पष्ट हो सके। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि अदालत भी इस विवाद के राजनीतिक प्रभाव को समझ रही है और इसे लंबित नहीं रखना चाहती।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला तकनीकी रूप से भले ही एक कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का हो, लेकिन इसके व्यापक राजनीतिक निहितार्थ हैं। चुनाव चिह्न किसी भी पार्टी की पहचान का अहम हिस्सा होता है और उस पर नियंत्रण खोना या विवाद में फंसना सीधे तौर पर चुनावी प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

तमिलनाडु जैसे राज्य में, जहां क्षेत्रीय दलों की मजबूत पकड़ है, वहां इस तरह का आंतरिक विवाद पार्टी के जनाधार को कमजोर कर सकता है। पीएमके पहले ही गठबंधन राजनीति का हिस्सा रही है और इस समय एनडीए के साथ सीट बंटवारे में शामिल है। ऐसे में पार्टी के भीतर की यह खींचतान गठबंधन की रणनीति पर भी असर डाल सकती है।

यह मामला भारतीय राजनीति में परिवार आधारित दलों की संरचना और उनके भीतर नेतृत्व संघर्ष की एक और मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। कई बार इस तरह के विवाद पार्टी की दिशा और भविष्य दोनों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि संगठनात्मक एकता कमजोर पड़ जाती है।

फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गेंद सिविल कोर्ट के पाले में चली गई है, जहां इस विवाद का अंतिम समाधान तलाशा जाएगा। सभी की नजर अब इस बात पर है कि अदालत कितनी जल्दी इस मामले का निपटारा करती है और क्या चुनाव से पहले पीएमके के भीतर की स्थिति स्पष्ट हो पाती है या नहीं।

महिला आरक्षण पर निर्णायक कदम की तैयारी संसद में नई राजनीतिक बिसात बिछने के संकेत

नई दिल्ली। देश की राजनीति में लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण का मुद्दा अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की दिशा में ठोस पहल शुरू कर दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानून में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है, जिससे वर्षों से अटकी इस व्यवस्था को जल्द अमल में लाया जा सके।

सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार किसी लंबी संवैधानिक प्रक्रिया या नई जनगणना का इंतजार करने के बजाय पहले से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर ही आरक्षण लागू करना चाहती है। यही कारण है कि प्रस्तावित संशोधन में नई जनगणना और परिसीमन से जुड़ी शर्तों को हटाकर 2011 की जनगणना के आधार पर व्यवस्था लागू करने की योजना बनाई जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ही महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण का लाभ मिल सकता है।

इस दिशा में राजनीतिक सहमति बनाने के लिए सरकार ने विभिन्न दलों के साथ बातचीत का दौर भी शुरू कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीजद, शिवसेना (यूबीटी), राकांपा (एसपी), वायएसआर कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों के नेताओं से चर्चा की है। आने वाले दिनों में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों से भी संवाद की प्रक्रिया तेज होने की संभावना है।

हालांकि विपक्ष ने इस पहल का सीधे तौर पर विरोध नहीं किया है, लेकिन उसने प्रक्रिया को लेकर सवाल जरूर उठाए हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि वे महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, लेकिन सरकार को इस मुद्दे पर पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि सरकार एक सर्वदलीय बैठक बुलाए, जिसमें प्रस्तावित संशोधन पर विस्तार से चर्चा हो और सभी दलों को अपनी राय रखने का अवसर मिले।

सरकार की योजना के अनुसार, इस संशोधन के बाद लोकसभा की कुल सीटों में भी बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। वर्तमान में जहां लोकसभा में 543 सीटें हैं, वहीं प्रस्तावित बदलाव के बाद यह संख्या बढ़कर 816 तक पहुंच सकती है। इसमें से लगभग 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह बदलाव न केवल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाएगा, बल्कि संसद के स्वरूप को भी व्यापक रूप से बदल देगा।

सीटों की संख्या बढ़ाने के पीछे सरकार का तर्क यह है कि मौजूदा सीटों में कटौती किए बिना आरक्षण लागू किया जाए, ताकि किसी भी क्षेत्रीय या राजनीतिक असंतुलन की स्थिति न बने। साथ ही, राज्यों में भी इसी अनुपात में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 से बढ़कर 120 तक पहुंच सकती हैं, जबकि बिहार में 40 से बढ़कर 60 और तमिलनाडु में 39 से बढ़कर लगभग 58 या 59 सीटें हो सकती हैं।

इस प्रस्ताव का एक अहम पहलू यह भी है कि आरक्षित सीटों का निर्धारण शुरुआत में लॉटरी के जरिए किया जाएगा और बाद में रोटेशन प्रणाली के तहत उन्हें बदला जाएगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आरक्षण का लाभ सभी क्षेत्रों को समय-समय पर मिलता रहे और किसी एक क्षेत्र में स्थायी रूप से सीट आरक्षित न रह जाए।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीति निर्माण में नए दृष्टिकोण सामने आएंगे और सामाजिक संतुलन को भी मजबूती मिलेगी। हालांकि, इसके साथ ही यह भी जरूरी होगा कि आरक्षण केवल संख्या तक सीमित न रह जाए, बल्कि महिलाओं को वास्तविक निर्णय प्रक्रिया में भी प्रभावी भूमिका मिले।

दूसरी ओर, इस प्रस्ताव से जुड़ी चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक सहमति की है, क्योंकि सीटों के पुनर्विन्यास और संख्या में वृद्धि से कई राज्यों और दलों के हित प्रभावित हो सकते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या के आधार पर सीटों के बंटवारे को लेकर पहले भी विवाद रहा है, ऐसे में सरकार को संतुलन बनाए रखना होगा।

इसके अलावा, परिसीमन की प्रक्रिया भी एक जटिल मुद्दा है। यदि इसे 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो यह देखना होगा कि क्या सभी राज्यों को यह स्वीकार्य होगा। हालांकि सरकार का मानना है कि चूंकि यह जनगणना कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के समय हुई थी, इसलिए विपक्ष को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

फिलहाल, संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस सप्ताह के अंत तक संसद में संशोधन विधेयक पेश कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो यह न केवल संसद के मौजूदा सत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक कदम होगा, बल्कि आने वाले चुनावों की दिशा भी तय कर सकता है।

कुल मिलाकर, महिला आरक्षण को लागू करने की यह पहल भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल इस पर किस तरह की सहमति बनाते हैं और क्या यह ऐतिहासिक बदलाव जल्द ही हकीकत बन पाता है या फिर एक बार फिर किसी राजनीतिक गतिरोध का शिकार हो जाता है।

संपादकीय

हिमाचल में बचत की कोशिश कारगर नहीं

हिमाचल प्रदेश आज एक ऐसे आर्थिक दौर से गुजर रहा है, जहां प्रतीकात्मक फैसलों और वास्तविक सुधारों के बीच का अंतर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ नौकरशाहों के वेतन में कटौती का हालिया निर्णय इसी संदर्भ में चर्चा का विषय बना हुआ है। यह निर्णय सतह पर एक जिम्मेदार और संवेदनशील कदम प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे गहराई से परखा जाता है, तो यह अधिक एक राजनीतिक संदेश के रूप में सामने आता है, न कि आर्थिक संकट के ठोस समाधान के रूप में।

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री के वेतन में 50 प्रतिशत, मंत्रियों के वेतन में 30 प्रतिशत और विधायकों के वेतन में 20 प्रतिशत की कटौती छह महीने के लिए लागू की है। इस निर्णय को जनता के बीच यह संदेश देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है कि सरकार भी कठिन समय में अपने खर्चों को सीमित करने के लिए तैयार है। निस्संदेह, यह कदम नैतिक दृष्टि से सराहनीय कहा जा सकता है, क्योंकि यह नेतृत्व की जवाबदेही को दर्शाता है। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से इसका प्रभाव सीमित ही रहने वाला है। यदि हम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति पर नजर डालें, तो स्पष्ट होता है कि राज्य का राजकोषीय घाटा हजारों करोड़ रुपये में है। ऐसे में वेतन कटौती से होने वाली बचत, जो अनुमानतः कुछ सौ करोड़ रुपये के भीतर ही सीमित रहेगी, इस विशाल घाटे के सामने नगण्य है। यह तथ्य इस बात को रेखांकित करता है कि यह कदम संकट की गंभीरता के मुकाबले अपर्याप्त है। इससे न तो राज्य की वित्तीय सेहत में कोई बड़ा सुधार होगा और न ही दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित की जा सकेगी। यह भी महत्वपूर्ण है कि इस संकट को अचानक उत्पन्न हुई स्थिति के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक चुनौतियां वर्षों से विकसित हो रही संरचनात्मक समस्याओं का परिणाम हैं। राज्य की आय का एक बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर रहा है। विशेष रूप से राजस्व घाटा अनुदान की समाप्ति ने इस निर्भरता को उजागर कर दिया है। जब तक यह अनुदान उपलब्ध था, तब तक राज्य अपनी वित्तीय कमजोरियों को संतुलित करने में सक्षम था, लेकिन इसके समाप्त होते ही वास्तविक स्थिति सामने आने लगी। राज्य के व्यय ढांचे की बात करें तो इसमें वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे निश्चित खर्चों का दबदबा है। ये ऐसे खर्च हैं जिन्हें कम करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि वे प्रशासनिक और सामाजिक दायित्वों से जुड़े होते हैं। इस कारण सरकार के पास व्यय में कटौती के सीमित विकल्प ही बचते हैं। ऐसे में वेतन कटौती जैसे निर्णय केवल सतही समाधान प्रदान करते हैं और मूल समस्याओं को छू भी नहीं पाते। वास्तविकता यह है कि हिमाचल प्रदेश को इस वित्तीय संकट से उबारने के लिए व्यापक और संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है। सबसे पहले, राज्य को अपने राजस्व स्रोतों को मजबूत करना होगा। पर्यटन, जलविद्युत और बागवानी जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं, जिनका अभी तक पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देकर और राजस्व संग्रहण की दक्षता बढ़ाकर राज्य अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकता है। इसके साथ ही, कर आधार का विस्तार भी आवश्यक है। वर्तमान में राज्य की कर प्रणाली सीमित दायरे में काम कर रही है। यदि इसे व्यापक बनाया जाए और कर संग्रहण में पारदर्शिता व दक्षता लाई जाए, तो राजस्व में वृद्धि संभव है। यह कदम राज्य को केंद्र पर निर्भरता कम करने में भी मदद करेगा। सब्सिडी व्यवस्था का पुनर्गठन भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कई बार सब्सिडी का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता, जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत होती है। यदि सब्सिडी को लक्षित और युक्तिसंगत बनाया जाए, तो इससे न केवल व्यय में कमी आएगी, बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता देना आवश्यक है। सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और डिजिटल अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में निवेश से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। यह दीर्घकाल में राजस्व सृजन का आधार तैयार करता है, जो किसी भी राज्य की आर्थिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। इस पूरे परिदृश्य का एक व्यापक पहलू भारत के संघीय ढांचे से भी जुड़ा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों के सामने विशेष भौगोलिक और आर्थिक चुनौतियां होती हैं। उनकी राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित होती है, जबकि विकास की लागत अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसे में केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता उनके लिए जीवनरेखा के समान होती है। लेकिन जब इस सहायता में अनिश्चितता होती है, तो उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को अधिक संतुलित और पारदर्शी बनाया जाए। राज्यों को मिलने वाली सहायता का ढांचा ऐसा होना चाहिए, जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखे और उन्हें दीर्घकालिक योजना बनाने में सक्षम बनाए। अंततः, वेतन कटौती जैसे कदम सरकार को अल्पकालिक राहत और नैतिक आधार प्रदान कर सकते हैं, लेकिन वे स्थायी समाधान नहीं हैं।

भगत सिंह के मार्क्सवादी विचारों की तार्किकता

> वर्ष 1925 से 1928 के बीच, भगत सिंह ने बहुत ज्यादा पढ़ा; उन्होंने रूसी क्रांति व सोवियत संघ पर लिखी किताबें पढ़ीं। 1920 के दशक में, क्रांतिकारी आंदोलनों पर सबसे अधिक जानकारी रखने वालों में भगत सिंह का नाम भी शामिल था।

'भगत सिंह न केवल भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारी समाजवादियों में से एक थे, बल्कि वे शुरुआती मार्क्सवादी विचारकों-सिद्धांतकारों में से भी एक थे। उनका बाद वाला पहलू अपेक्षाकृत कम ज्ञात है, फलतः प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और सांप्रदायिक लोग अपनी राजनीतिक विचारधारा हेतु भगत सिंह और साथियों—जिनमें चंद्रशेखर आज़ाद भी शामिल हैं—के नाम-यश का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं।'

उपरोक्त शब्द मेरे मार्गदर्शक, प्रो. बिपन चंद्र ने भगत सिंह के बीस-पृष्ठों वाले लेख 'मैं नास्तिक क्यों हूं' की प्रस्तावना में लिखे थे; लेख पंजाबी कवि अमरजीत चंदन ने 1979 में खोजा था। पिछले 40 वर्षों में, भगत सिंह का यह ऐतिहासिक मूल्यांकन निर्विवाद तथ्य की ताकत पा चुका है। पाठकों के मानस में बैठाने को उनकी 'जेल नोटबुक' के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं कि यह किताब प्रतिष्ठित विचारकों और दार्शनिकों के विचारों की भगत सिंह द्वारा की गई पड़ताल एक नई खिड़की खोलती है।

गदर आंदोलन के इतिहासकार हरीश पुरी लिखते हैं—'हालांकि जहां कहीं से उन्होंने ये नोट्स या उद्धरण उठाए, उन स्रोतों या किताबों के बारे में दी गई अधूरी जानकारियों ने एक उलझन भरा प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। यानी, ये उद्धरण किन लेखकों विशेष से, किन किताबों के किस संस्करण से लिए गए थे? फलतः भगत सिंह जेल में जिन महान विचारकों की किताबों-रचनाओं का अध्ययन कर पाए थे, उसको लेकर उनके प्रशंसक विद्वानों ने कई मनगढ़ंत दावे-बेबुनियाद अटकलें लगा लीं।'

1925 से 1928 के बीच, भगत सिंह ने बहुत ज्यादा पढ़ा; उन्होंने रूसी क्रांति व सोवियत संघ पर लिखी किताबें पढ़ीं। 1920 के दशक में, क्रांतिकारी आंदोलनों पर सबसे अधिक जानकारी रखने वालों में भगत सिंह का नाम भी शामिल था। वर्ष 1928 के अंत में उन्होंने व साथियों ने समाजवाद को अपनी गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य मान अपने संगठन का नाम 'हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन' से बदलकर 'हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' कर दिया था।

सवाल है कि क्या भगत सिंह को मार्क्सवाद से भारतीय राष्ट्रवाद की समकालिक राजनीति, मज़दूर वर्ग के आंदोलनों और ऐतिहासिक-सामाजिक यथार्थ को समझने में मदद मिली? मार्क्सवाद पर ऐसी महारत, जो सिर्फ़ किताबों में लिखी बातों को समझने का एक अभ्यास भर हो, वह 'ब्राह्मणवादी मार्क्सवाद' बनकर ही रह जाएगा; जब तक कि वह पार्टी के बुद्धिजीवियों को 'व्यावहारिक सिद्धांत' का एक ढांचा पेश कर, समय की सामाजिक सच्चाई से निष्पक्ष होकर जुड़ने में मदद न करे।

तो फिर, किसे मार्क्सवादी विचारक कहा जा सकता है? यह सवाल इटली के बुद्धिजीवी एंटोनियो ग्राम्शी की याद दिलाता है, जो ठीक भगत सिंह की तरह ही, और ठीक उसी समय, फ़ासीवादी मुसोलिनी की जेल में, 1937 में अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले तक कैद में रहे। इन कठिन परिस्थितियों में भी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की ठोस समस्याओं, उसकी असफलताओं और सफलताओं को समझने-सुलझाने के लिए अपना पढ़ने-लिखने का काम जारी रखा।

इन दिनों, पश्चिम एशियाई संकट की बहसों में, ट्रंप और नेतन्याहू के रणनीतिक लक्ष्यों को समझाने के लिए 'आधीनता की अवधारणा' का खूब ज़िक्र किया जाता है। तथ्य यह है कि वहां सत्ता परिवर्तन के लिए अमेरिका और इस्राइल को सबसे पहले ईरानी समाज पर हावी होकर उसे पूरी तरह से झुका डालना होगा। जब कोई राष्ट्र या समाज, किसी दूसरे सामाजिक समूह द्वारा शासित होने के लिए ज़बरदस्ती से मजबूर किया जाता है, तभी 'आधीनता' स्थापित हो पाती है। पराजित लोगों के लिए यह बहुत ही कठिन क्षण होता है। उदाहरणार्थ, 1857 के नाराज़ भारतीय विद्रोहियों को, ब्रिटिश सेना और सिख सैनिकों द्वारा हराए जाने के बाद, ब्रिटिश राज की आधीनता स्वीकार करने के लिए तब राज़ी हो पाए, जब उन्होंने देखा कि उनके कुलीन वर्ग को राज का हिस्सा बना लिया गया है। सर सैयद अहमद खान, जिन्हें 1888 में ब्रिटिश सरकार द्वारा 'नाइट कमांडर ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ द स्टार ऑफ़ इंडिया' के सम्मान से नवाज़ा गया था– उन्हें अपने साथ जोड़कर नए शासकों की आधीनता स्वीकार करने के लिए राजी किया गया। उन्होंने भारतीय मुसलमानों के बीच विमर्श रखा कि समुदाय की तरक्की के लिए सहयोग, अथवा ब्रिटिश आधीनता को स्वीकार्य करना जरूरत है। भाव यह कि सत्ता परिवर्तन के बिना आधीनता कायम नहीं की जा सकती। भगत सिंह का मानना था कि गांधी का अहिंसा का मार्ग, भारत को अर्ध-अधीनस्थ राष्ट्र बनाने में सहयोग करने जैसा है।

इसीलिए साइमन विरोधी प्रदर्शनों के दौरान, भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज का दोष ब्रिटिश अधिकारी जेम्स स्कॉट पर मढ़ा, लेकिन वे इस बात से अनजान रहे कि असल में यह पंजाब पुलिस के सिपाही थे, जिन्होंने उन्हें पीटा था।

भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों का मानना था कि ब्रिटिश वर्चस्व की ताकत इतनी भर है कि अगर गांधी आड़े न आएं, तो वे ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएंगे। परंतु वे यह नहीं देख पाए कि वही ब्रिटिश राज उन्हें मीडिया के ज़रिए अपने विचारों का प्रचार करने की अनुमति कैसे और क्यों कर दे रहा है, उन्हें अदालत तक में क्रांतिकारी गीत गाने की छूट क्यों मिली, अथवा जेल अधिकारी उन्हें किताबें पढ़ने की इजाज़त क्यों देते हैं।

यह संक्षिप्त चर्चा इस तथ्य को रेखांकित करती है कि भगत सिंह को मार्क्सवाद की केवल बुनियादी समझ ही थी। वे आधुनिक, केंद्रीकृत और नौकरशाही-आधारित राज्य की अत्यंत जटिल वास्तविकता के साथ रचनात्मक रूप से जुड़कर कोई नया वैचारिक ढांचा गढ़ने या अपनाने में असमर्थ रहे; जबकि इस राज-व्यवस्था को करोड़ों भारतीयों की सहमति से ही वैधता प्राप्त थी। वास्तव में, वे अकाली आंदोलन (1925) के अनुभवों को भी आत्मसात नहीं कर पाए—जो कि इस उपमहाद्वीप का पहला महान और शांतिपूर्ण जन-आंदोलन था, जिसे ब्रिटिश अधिकारियों ने कुचलने का प्रयास किया था। दरअसल, भगत सिंह केवल असफल 'ग़दर आंदोलन' को ही समझ पाए। लेकिन उसकी असफलता से कोई सबक सीखने के बजाय, उन्होंने आंख मूंदकर ग़दरपंथियों का मार्ग चुना।

प्रेरणा

अटूट आत्मबलः विजय का अदृश्य शस्त्र

इतिहास के पन्नों में अनेक ऐसी घटनाएं दर्ज हैं, जो यह साबित करती हैं कि किसी भी युद्ध की असली जीत तलवारों या हथियारों से नहीं, बल्कि मन और आत्मबल से होती है। जब व्यक्ति या समाज अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तो वह असंभव दिखने वाली परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में मोड़ सकता है। आत्मबल ही वह अदृश्य ऊर्जा है, जो साधारण मनुष्य को असाधारण बना देती है और पराजय की कगार पर खड़े समाज को विजय के शिखर तक पहुंचा देती है।

प्राचीन काल में यूरोप का एक बड़ा हिस्सा यूनान की शक्तिशाली सेनाओं के आतंक से भयभीत था। यूनान की सेना को अजेय माना जाता था। उनका नाम सुनते ही विरोधी सेनाएं मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान लेती थीं। युद्ध शुरू होने से पहले ही हार की भावना उनके मन में घर कर जाती थी। यह भय इतना गहरा था कि कई राज्यों ने बिना संघर्ष किए ही आत्मसमर्पण कर दिया। धीरे-धीरे यह धारणा बन गई कि यूनानी सेना को हराना असंभव है।

इसी समय जूलियस सीज़र ने इस स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने पाया कि यूनानियों की असली ताकत उनकी सैन्य शक्ति से ज्यादा उनके विरोधियों की मानसिक कमजोरी है। लोग खुद को कमजोर और यूनानियों को अजेय मान चुके थे। यह आत्महीनता ही पराजय का सबसे बड़ा कारण बन चुकी थी। सीज़र ने समझा कि यदि इस मानसिकता को बदल दिया जाए, तो युद्ध का परिणाम भी बदल सकता है।

सीज़र ने एक अनोखा और प्रभावशाली उपाय अपनाया। उन्होंने रोम की दीवारों, गलियों और सार्वजनिक स्थलों पर एक वाक्य लिखवाया—"यूनानी फौजें तभी तक अजेय हैं, जब तक हम उनके सामने घुटने टेके बैठे हैं। आओ तनकर खड़े हो जाएं।" यह केवल एक वाक्य नहीं था, बल्कि यह रोम के लोगों के भीतर सोई हुई आत्मशक्ति को जगाने का मंत्र था। इस संदेश ने धीरे-धीरे लोगों के मन में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया।

रोम की जनता और सैनिकों के भीतर आत्मविश्वास की एक नई लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने यह समझ लिया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि उनके भीतर चल रही है। जैसे ही उन्होंने अपने मन से डर को निकाल फेंका और आत्मबल को अपनाया, उनकी सोच बदल गई। अब वे यूनानियों को अजेय नहीं, बल्कि एक सामान्य शत्रु के रूप में देखने लगे।

जब युद्ध का समय आया, तो रोम की सेना पहले की तरह भयभीत नहीं थी। वे आत्मविश्वास और साहस से भरे हुए थे। उन्होंने पूरी ताकत और रणनीति के साथ युद्ध लड़ा। परिणामस्वरूप, जो यूनानी सेना अब तक अजेय मानी जाती थी, उसे पराजय का सामना करना पड़ा। यह जीत केवल सैन्य कौशल की नहीं थी, बल्कि आत्मबल की शक्ति की जीत थी।

यह घटना हमें यह सिखाती है कि किसी भी चुनौती का सामना करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मन की होती है। जब हम अपने भीतर आत्मविश्वास और दृढ़ता को विकसित करते हैं, तो हम किसी भी कठिन परिस्थिति को पार कर सकते हैं। इसके विपरीत, यदि हम स्वयं को कमजोर मान लेते हैं, तो छोटी-सी समस्या भी हमारे लिए बड़ी बन जाती है।

आज के समय में भी यह शिक्षा उतनी ही प्रासंगिक है। जीवन के हर क्षेत्र में—चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, या व्यक्तिगत जीवन—आत्मबल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार हम असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। हम पहले से ही मान लेते हैं कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। यही सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है।

यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और सकारात्मक सोच को अपनाएं, तो हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं। आत्मबल हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देता है, बल्कि हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा भी देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम जो चाहते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं।

आत्मबल का विकास एक दिन में नहीं होता। इसके लिए निरंतर अभ्यास और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक बनाना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का प्रयास करना होगा, और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना होगा। जब हम ऐसा करते हैं, तो धीरे-धीरे हमारा आत्मबल मजबूत होता जाता है।

इसके साथ ही, हमें यह भी समझना चाहिए कि आत्मबल केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए भी आवश्यक है। जब एक समाज के लोग आत्मविश्वासी और मजबूत होते हैं, तो वे मिलकर बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं, जहां एकजुट और आत्मबल से भरे समाज ने असंभव को संभव कर दिखाया है।

अंततः, यह कहा जा सकता है कि आत्मबल ही वह शक्ति है, जो हमें हमारी वास्तविक क्षमता से परिचित कराती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उन्हें बदलने की क्षमता रखते हैं। जिस दिन हम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लेंगे, उस दिन हमारे लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहेगा।

इसलिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बाहरी संसाधनों से ज्यादा अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। जब हम तनकर खड़े होते हैं और अपने आत्मबल पर विश्वास करते हैं,

लिटिल इंडिया पर मिसाइल दाग ईरान ने दिया मैसेज या कर दी बड़ी भूल, अब Samson Option का इजरायल करेगा इस्तेमाल? सब हो जाएगा खत्म

किसी भी चरण का युद्ध बेहद गंभीर मामला होता है। खासकर जब इसमें इज़राइल और अमेरिका शामिल हों। लेकिन ईरान पर थोपा गया यह युद्ध पिछले 48 घंटों में अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। अब स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही है। पिछले 48 घंटों में दो बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिनसे पता चलता है कि यह युद्ध पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। इसके वैश्विक परिणाम भी अब स्पष्ट हो गए हैं। पहली बात, इस युद्ध में अब परमाणु शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। खुद को विजेता घोषित करने के बाद, डोनाल्ड ट्रम्प ने एक और अल्टीमेटम दिया है और यह अल्टीमेटम बेहद हताशा भरा है। अगर ईरान इस अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अगले 24-48 घंटों में भारी उथल-पुथल मच सकती है।ईरान ने इजराइल के दक्षिणी इलाके में मौजूद डिमोना और अराद में मिसाइल अटैक किया है। 100 लोगों के घायल होने की खबर है। डिमोना वो जगह है जहां से 13 किमी की दूरी पर नेगेव रेगिस्तान है। नेगेव रेगिस्तान जहां पर इजराइल का नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इस लोकेशन के इतने करीब मिसाइल को इंटरसेप्ट ना कर पाना इजराइल की बड़ी चूक मानी जा रही है। सबसे पहले, परमाणु मुद्दे पर बात करते हैं। इस पर काफी हंगामा मचा हुआ है। अगर आप मीडिया पर गौर करें तो आपको लगेगा कि ईरान ने इज़राइल के परमाणु संयंत्र पर हमला किया है। लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कि यह हमला जानबूझकर न किया गया हो। डिमोना के पास स्थित शिमोन पेरेस परमाणु अनुसंधान संयंत्र पर हमला नहीं हुआ है। बल्कि डिमोना शहर पर हमला हुआ है, जहां उस संयंत्र में काम करने वाले लोग रहते होंगे। यह हमला जवाबी कार्रवाई के तौर पर किया गया है... ठीक उसी तरह जैसे अमेरिका ने नतान्ज़ पर फिर से हमला किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इज़राइल के परमाणु संयंत्र के पास स्थित डिमोना शहर पर हमला कर दिया। और यह हमला एक संदेश देने के उद्देश्य से क्यों किया गया? अराद पर भी हमला किया गया है, लेकिन डिमोना पर हुआ यह हमला इतना खास क्यों है? मिसाइल इंटरसेप्ट में हुई चूक पर इजराइल क्या बोला और डेमोना का भारत से क्या ताल्लुक है? इसे लिटिल इंडिया क्यों कहते हैं? आज इसी का एमआरआई स्कैन करेंगे। अगर किसी परमाणु संयंत्र पर हमला नहीं होता, तो यह इतना खास क्यों है? ज़रा सोचिए, अगर कोई देश आकर हमारे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के पास हमला कर दे, तो हमारे देश की क्या प्रतिक्रिया होगी? क्योंकि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की तरह ही डिमोना में भी उनका एक परमाणु संयंत्र है। इसी अनुसंधान केंद्र ने इज़राइल को पहले 13 परमाणु हथियार मुहैया कराए थे। वहीं से यूरेनियम का उत्पादन हुआ था और वहीं से, मुझे लगता है 1967 में, इज़राइल को परमाणु हथियार मिले थे। आज जवाबी कार्रवाई के तौर पर उसी संयंत्र के पास एक बम गिराया गया। ईरान का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। कि अगर हमारे परमाणु संयंत्रों पर हमला होता है, तो आपके परमाणु संयंत्र भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं हैं।

अराद शहर में ईरानी मिसाइल गिरने के बाद तबाही का भारी मजर देखने को मिला। रिहायशी इमारतो के बीच हुए इस धमाके में कई लोग घायल हो गए। जेरुशलम पोस्ट के मुताबिक, एक व्यक्ति ने बताया, अलर्ट के बाद हम शेल्टर में गए थे। कुछ देर बाद जोरदार धमाका हुआ, पूरा घर हिल गया। बाहर निकलने पर घर के खिड़की दरवाजे उखड़े नजर आए। सामान टूटकर बिखरा मिला। वही, राहतकर्मियों ने बताया, घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। अधिकारियों के मुताबिक कम से कम तीन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है।

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो दुनिया भर में न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर नजरें रखती है। उसने अपने पोस्ट में लिखा आईएईए को इजराइल के डिमोना शहर में मिसाइल हमले की जानकारी है। नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। आसपास के देशों से मिली जानकारी के मुताबिक रेडिएशन का स्तर सामान्य है और कोई भी एब्नॉर्मल रेडिएशन की सूचना अभी तक हमें नहीं मिली है। इन हालातों पर हमारी बारीकी से नजर है। डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रासी ने कहा है कि दोनों पक्षों को सैन्य संयम बरतना चाहिए। खासकर परमाणु केंद्रों के आसपास के इलाके में। जानकारी के लिए बता दें कि डिमोना के पास मौजूद नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर को डिमोना रिएक्टर नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि यहां इसराइल ने अपने परमाणु हथियार छिपा रखे हैं। पर यह अनडिक्लेयर्ड है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि यहां केवल रिसर्च प्रोग्राम चलता है।

डिमोना इस्राइल का परमाणु केंद्र है। साथ ही भारतीय-यहूदी समुदाय की बड़ी आबादी के चलते इसे लिटिल इंडिया भी कहा जाता है। तुर्किये की अनादोलु न्यूज एजेंसी के अनुसार, ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि अगर अमेरिका और इस्राइल युद्ध बढ़ाते हैं, तो डिमोना रिएक्टर को निशाना बनाया जाएगा। डिमोना रिएक्टर को शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहा जाता है। यह इजरायल के परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ माना जाता है। यह दक्षिणी इजरायल के नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। परिसर करीब 36 वर्ग किलोमीटर में फैला है।

अभियान

रामः भावना, भक्ति और मानवता के विराट संगम की जीवंत परंपरा

जब रामनवमी का पावन पर्व आता है, तो अयोध्या की हवा तक बदल जाती है। सरयू किनारे से लेकर मंदिरों की घंटियों तक, हर ओर एक ही स्वर गूंजता है—"भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कौसल्या हितकारी।" यह केवल एक धार्मिक उद्घोष नहीं, बल्कि आस्था, प्रेम और सांस्कृतिक एकता का वह अदृश्य सूत्र है, जो करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ देता है। भगवान राम केवल पूजा के विषय नहीं, बल्कि भारतीय मानस की धड़कन हैं, जो समय के साथ बदलती नहीं, बल्कि और अधिक व्यापक होती जाती हैं।

राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे किसी एक परिभाषा में सीमित नहीं किए जा सकते। रामायण में वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं—आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा। लेकिन लोकजीवन में वे इससे कहीं अधिक हैं। वे किसी के लिए दीनबंधु हैं, किसी के लिए संकटमोचक, तो किसी के लिए एक ऐसे मित्र, जो हर परिस्थिति में साथ खड़े रहते हैं। यही कारण है कि राम केवल देवता नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति बन जाते हैं।

अयोध्या की संत परंपरा सदियों से यह कहती आई है कि राम की छवि किसी एक व्यक्ति या संप्रदाय द्वारा तय नहीं की जा सकती। हर भक्त को यह अधिकार है कि वह अपनी भावना के अनुसार अपने राम की कल्पना करे। यही कारण है कि राम की भक्ति में विविधता का अद्भुत विस्तार देखने को मिलता है। कोई उन्हें सखा मानकर उनकी उपासना करता है, कोई उन्हें पति के रूप में देखता है, तो कोई उन्हें अपने बालक के रूप में अनुभव करता है। यह विविधता ही रामभक्ति को इतना जीवंत और व्यापक बनाती है।

कबीर जैसे संतों ने राम को किसी एक रूप में बांधने से इनकार कर दिया। उनके लिए राम वह परम सत्ता हैं, जो हर जगह विद्यमान हैं। कबीर की वाणी में यह स्पष्ट झलकता है—कभी वे राम को अपना प्रिय बताते हैं, तो कभी अपनी जननी। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध किया कि भक्ति का संबंध बाहरी रूपों से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव से होता है।

इसी प्रकार महात्मा गांधी के लिए राम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं थे, बल्कि नैतिकता और सत्य के प्रतीक थे। उनका प्रिय भजन "रघुपति राघव राजा राम" केवल भक्ति का गीत नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता का संदेश था। "ईश्वर अल्ला तेरो नाम" के माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि राम किसी एक धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे मानवता के साझा आदर्श हैं।

रामकथा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी वैश्विकता है। यह केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के अनेक देशों में विभिन्न रूपों में जीवित है। इंडोनेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे देशों में रामकथा का मंचन होता है। इन देशों में, जहां बहुसंख्यक लोग अन्य धर्मों के अनुयायी हैं, वहां भी राम की कथा को उतनी ही श्रद्धा और उत्साह से प्रस्तुत किया जाता है।

इन देशों की रामकथाओं में स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। विशेष रूप से फिलीपींस की रामकथा में इस्लामी तत्वों का समावेश यह दर्शाता है कि किस प्रकार एक कथा समय और स्थान के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन उसका मूल संदेश वही रहता है। यह विविधता रामकथा को और अधिक समृद्ध बनाती है।

इतिहास के पन्नों में भी राम की यह सर्वसमावेशी छवि देखने को मिलती है। जब 1856 में अंग्रेजों ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह को सत्ता से हटाकर निर्वासित कर दिया, तब अयोध्या के लोगों ने उनके लिए भगवान राम से प्रार्थना की। यह घटना उस गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक है, जिसमें धर्म और संस्कृति के बीच कोई भेदभाव नहीं था। नवाबों ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अयोध्या के मंदिरों को दान और सहायता प्रदान की।

भक्तिकाल के संत कवियों ने राम को अपनी भक्ति का केंद्र बनाया और उन्हें जन-जन तक पहुंचाया। तुलसीदास की पंक्ति "जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी" यह दर्शाती है कि राम की अनुभूति हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई उन्हें सगुण साकार रूप में पूजता है, तो कोई उन्हें निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में अनुभव करता है।

सूरदास, मीरा बाई और संत रैदास जैसे भक्तों ने भी राम नाम की महिमा को स्वीकार किया। मीरा, जो मुख्यतः कृष्णभक्त थीं, उन्होंने भी राम नाम को उतना ही महत्व दिया। उनके लिए भक्ति का मूल तत्व प्रेम था, और इस प्रेम में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था।

संत रैदास ने भक्ति को सरल और सहज बनाने का प्रयास किया। उनके अनुसार "मन ही पूजा, मन ही धूप" है। यह विचार भक्ति को बाहरी आडंबरों से मुक्त कर उसे आंतरिक अनुभव का विषय बना देता है। इसी प्रकार संत मलूकदास ने भी राम नाम की महिमा का गुणगान किया और लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। आधुनिक युग में भी राम की प्रासंगिकता बनी हुई है। मैथिलीशरण गुप्त ने अपने महाकाव्य "साकेत" में राम को एक मानवीय दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। उन्होंने राम से प्रश्न किया—"राम, तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?" यह प्रश्न राम के मानवीय और दैवीय दोनों स्वरूपों को समझने का प्रयास है। भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भी अपनी रचनाओं में राम के प्रति अपनी गहरी भावनाओं को व्यक्त किया। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने "राम की शक्ति पूजा" के माध्यम से राम को संघर्ष और आत्मबल के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी यह रचना स्वतंत्रता संग्राम के समय लोगों में साहस और आत्मविश्वास भरने का माध्यम बनी।

राम की यह यात्रा केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और मानवीय भी है। वे हर युग में नए अर्थ लेकर आते हैं और हर पीढ़ी को नई दिशा देते हैं। उनकी भक्ति में विविधता है, लेकिन उस विविधता में भी एक अद्भुत एकता छिपी हुई है।

अंततः, भगवान राम केवल एक नाम नहीं, बल्कि एक विचार हैं—एक ऐसा विचार, जो हमें सत्य, धर्म, करुणा और प्रेम के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। "भये प्रगट कृपाला दीनदयाला" का उद्घोष हमें यह याद दिलाता है कि जब-जब मानवता संकट में होगी, तब-तब राम का यह स्वरूप हमारे भीतर जागृत होगा और हमें सही मार्ग दिखाएगा।

यही कारण है कि राम केवल अतीत के नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के भी मार्गदर्शक हैं। उनकी महिमा अनंत है, उनकी छवियां अनगिनत हैं और उनकी प्रासंगिकता शाश्वत है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

ई-नगर पोर्टल : गुजरात शहरी विकास मिशन अंतर्गत नागरिक सेवाओं के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म

वर्ष 2025-26 में ई-नगर पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए और 1031 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई

▶▶ नागरिकों के लिए कर भुगतान, लाइसेंस आवेदन, विवाह पंजीकरण, मकान अनुमति, पानी व ड्रैनेज कनेक्शनों के संचालन जैसी सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध

▶▶ ई-नगर पोर्टल पर कुल मिलाकर 1.24 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए और 6076 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई

गांधीनगर : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत में डिजिटल परिवर्तन का एक नया अध्याय शुरू हुआ है। टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग द्वारा प्रत्येक नागरिक का जीवन सरल बनाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया मिशन शुरू किया था। आज इंटरनेट की व्यापक पहुँच तथा सरकारी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध होने से आम नागरिक के रोजमर्रा के कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। गुजरात में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तथा नागरिक-केन्द्रित गवर्नेंस को नई ऊँचाइयाँ मिल रही हैं। नगर पालिका की विभिन्न सेवाएँ एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने के उद्देश्य से गुजरात शहरी विकास मिशन (जीयूडीएम) द्वारा ई-नगर पोर्टल लॉन्च किया गया था, जिसमें वर्ष 2025-26 में 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए हैं। उल्लेखनीय है कि ई-नगर पोर्टल अंतर्गत आम नागरिक शिकायत पंजीकरण, दुकान के लाइसेंस के लिए आवेदन, विवाह पंजीकरण, मकान की अनुमति, व्यवसाय कर, संपत्ति कर, एस्टेट रेंट भुगतान, हॉल बुकिंग, पानी तथा ड्रैनेज आदि कार्य घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। यह पोर्टल 24X7 ऑनलाइन एक्सेस, पेमेंट के लिए कार्ड, यूपीआई तथा नेट बैंकिंग जैसे विकल्प, रीयल-टाइम एप्लिकेशन ट्रैकिंग, मोबाइल एप्लिकेशन सपोर्ट प्रदान करता है और नागरिक प्रमाणपत्र तथा रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं; नागरिक इस पोर्टल का अधिक बेहतर तरीके से उपयोग कर सकें; इसके लिए नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा

है। यूजर्स जानकारी आसान से प्राप्त कर सकें; इसके लिए पोर्टल में एआई चैटबोट की सुविधा जोड़ी गई है। इसके अलावा, भाषिणी के सहयोग से ई-नगर पोर्टल अब 23 भाषाओं में उपलब्ध है, जिसके कारण विभिन्न भाषाएँ बोलने वाले लोगों के लिए इसका उपयोग सरल बना है।

गुजरात सरकार के ई-नगर प्रोजेक्ट के कारण नागरिक तथा प्रशासन के बीच संपर्क अधिक सरल एवं सुदृढ़ बना है। नागरिक अब किसी भी स्थान से फीस, टैक्स तथा अन्य शुल्कों का भुगतान कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं और प्रमाणपत्र ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, राज्य सरकार की एकीकृत डिजिटल व्यवस्था द्वारा नागरिकों को तमाम सेवाएँ एक ही स्थान पर मिलती हैं।

वर्ष 2025-26 के दौरान ई-नगर पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए

ई-नगर पोर्टल के कारण कागजी कार्य कम हुआ है। म्युनिसिपल ऑफिसों में लंबी कतारों में खड़े रहने की समस्या दूर हुई है और नागरिक सेवाएँ तेज व पारदर्शी बनी हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान पोर्टल पर 18 लाख से अधिक ट्रांजेक्शन दर्ज हुए हैं और 1031 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। वर्ष 2024-25 में 26 लाख ट्रांजेक्शन तथा 1522 करोड़ रुपए की आय दर्ज हुई। कुल मिलाकर इस प्लेटफॉर्म पर 1.24 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांजेक्शन हुए हैं और 6076 करोड़ रुपए से अधिक आय प्राप्त हुई है, जो दर्शाता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म का व्यापक उपयोग कर रहे हैं और उनका समय भी बच रहा है।

जूनागढ़–देलवाड़ा मीटरगेज ट्रेन का पुनः संचालन 25 मार्च से तथा जूनागढ़-चालाला मीटरगेज ट्रेन के समय में आंशिक परिवर्तन

यात्रियों की मांग एवं उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा जूनागढ़–देलवाड़ा मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन को पुनः संचालित करने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय परिचालनिक आवश्यकताओं एवं यात्री हितों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रेन संख्या 52951/52952 (देलवाड़ा–जूनागढ़–देलवाड़ा दैनिक मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन) का संचालन दिनांक 25 मार्च 2026 से पुनः प्रारंभ किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 52952 (जूनागढ़–देलवाड़ा दैनिक मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन) दिनांक 25.03.2026 से प्रारंभ होगी। यह ट्रेन जूनागढ़ से प्रातः 08:00 बजे प्रस्थान कर 14:40 बजे देलवाड़ा पहुंचेगी।

ट्रेन संख्या 52951 (देलवाड़ा–जूनागढ़ दैनिक मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन) दिनांक 26.03.2026 से प्रारंभ होगी। यह ट्रेन देलवाड़ा से प्रातः 11:00 बजे प्रस्थान कर सायं 17:25 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी।

यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में उना, गीरगढरा, हडमडिया, जामवाला, वलादर, प्राची, गीर हडमतिया, जाम्बूर, तालाला, चित्रावड, सासण गीर, कांसियानेश, सताधार, विसावदर, जूनी चावंड, बिलखा एवं तोरणिया स्टेशनों पर ठहरेगी।

इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09595/09596 (जूनागढ़–चालाला–जूनागढ़ दैनिक मीटरगेज पैसेंजर स्पेशल) के समय में दिनांक 25 मार्च 2026 से आंशिक संशोधन किया गया है। ट्रेन संख्या 09595 (जूनागढ़–चालाला दैनिक मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन) अब प्रातः 10:40 बजे के स्थान पर 11:30 बजे प्रस्थान करेगी तथा 14:10 बजे के स्थान पर 14:50 बजे चालाला पहुंचेगी। ट्रेन संख्या 09596 (चालाला–जूनागढ़ दैनिक मीटरगेज पैसेंजर ट्रेन) अब 14:40 बजे के स्थान पर 15:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा 17:35 बजे के स्थान पर 18:45 बजे जूनागढ़ पहुंचेगी।

साथ ही, ट्रेन संख्या 52933/52956 (जूनागढ़–वेरावल–जूनागढ़) दैनिक पैसेंजर को दिनांक 25 मार्च 2026 से अस्थायी रूप से निरस्त किया गया है।

पश्चिम रेलवे यात्रियों से अनुरोध करता है कि वे अपनी यात्रा की योजना अद्यतन समय-सारिणी के अनुसार बनाएं तथा रेलवे प्रशासन को सहयोग प्रदान करें।

गुजरात सरकार द्वारा आधिकारिक स्पष्टीकरण : राज्य में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध, अफवाहों से दूर रहने की नागरिकों से अपील

पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाने की आवश्यकता नहीं, राज्य के पास पर्याप्त बफर स्टॉक उपलब्ध : अपर मुख्य सचिव श्री मोना खंधार

गांधीनगर : गुजरात के कुछ शहरों में पेट्रोल और डीजल की कमी को लेकर फैल रही अफवाहों के बीच सोमवार को राज्य सरकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त बयान जारी कर आम जनता को महत्वपूर्ण विश्वास दिया है कि राज्य में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है।

इस संदर्भ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मोना खंधार ने कहा कि राज्य के सभी पेट्रोल पंपों पर आवश्यकता के अनुसार पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगाने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा राज्य में पर्याप्त ईंधन का 'बफर स्टॉक' भी उपलब्ध है, जिससे किसी प्रकार की घबराहट या जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है।

अपर मुख्य सचिव ने आगे कहा कि कुछ स्थानों पर पेट्रोल और डीजल की कमी संबंधी खबरें केवल अफवाह हैं। यदि कोई डीलर भंडार उपलब्ध होने के बावजूद जानबूझकर पंप बंद रखता है या जनता को परेशान करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसीएल) के स्टेट नोडल अधिकारी एवं कार्यकारी निदेशक श्री संजीब कुमार बेहेरा ने कहा कि गुजरात के सभी पेट्रोल-डीजल डिपो और टर्मिनलों में पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है। इसलिए नागरिकों को पेट्रोल पंपों पर कतारें लगाने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें किसी भी समय आवश्यक मात्रा में ईंधन प्राप्त होगा।

भारत पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने कहा कि तेल कंपनियों ने आपूर्ति के घंटों में वृद्धि की है और भंडार भी बढ़ाया गया है। साथ ही उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों या भ्रामक संदेशों से प्रभावित होकर पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं। गुजरात में ईंधन की कोई कमी नहीं है और भविष्य में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

नवयुग पालिका योजना से बदलेगा यूपी का शहरी चेहरा, योगी कैबिनेट के फैसलों से विकास को नई रफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास को नई दिशा देने की पहल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लोकभवन में आयोजित इस बैठक में कुल 39 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 37 को मंजूरी दी गई, जबकि 2 प्रस्तावों को फिलहाल स्थगित रखा गया। इस बैठक का सबसे अहम निर्णय "नवयुग पालिका योजना" को मंजूरी देना रहा, जिसे राज्य के संतुलित और समावेशी शहरी विकास की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार ने पहली बार नगर निगमों से बाहर के शहरी क्षेत्रों—विशेषकर नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों—को प्राथमिकता दी है। अब तक विकास का बड़ा हिस्सा बड़े शहरों तक सीमित था, लेकिन इस नई योजना के जरिए छोटे और मध्यम शहरों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इससे न केवल इन शहरों की आधारभूत संरचना मजबूत होगी, बल्कि रोजगार, निवेश और जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। नवयुग पालिका योजना के तहत प्रदेश के 58 जिला मुख्यालयों को सीधे लाभ मिलेगा। इनमें 55 नगर पालिका परिषद, 3 नगर पंचायतें और गौतमबुद्धनगर की दादरी नगर पालिका परिषद शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य इन शहरों को "मिनी स्मार्ट सिटी" के रूप में विकसित करना है, जहां डिजिटल सेवाएं, स्वच्छता, बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हों।

इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए राज्य सरकार ने 5 वर्षों में कुल 2916 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया है। हर साल लगभग 583.20 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि यह

पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की कोई भागीदारी नहीं होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों के जरिए शहरी विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।

योजना के तहत डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष जोर दिया जाएगा। ई-सेवाओं के विस्तार से नागरिकों को सरकारी कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। 'वन डे गवर्नेंस सेंटर' की स्थापना की जाएगी, जहां एक ही दिन में कई सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी, थीम पार्क, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे। परियोजनाओं के चयन और क्रियान्वयन के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया तय की गई है। जनपद स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी, जो स्थानीय जरूरतों के अनुसार परियोजनाओं का चयन करेंगी। इसके बाद राज्य स्तर की तकनीकी समिति उनकी जांच करेगी और अनुमोदन के बाद ही कार्य शुरू होगा। इससे पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए भी राहत भरे फैसले लिए गए। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2585 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में 160 रुपये अधिक है। इसके अलावा किसानों को गेहूं की उतराई, सफाई और छनाई के लिए 20 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त दिए जाएंगे। इससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। सरकार ने इस सीजन में 30 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसे बढ़ाकर 50 लाख टन तक किया जा सकता है। खरीद प्रक्रिया 30 मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन्हें अपनी उपज बेचने में आसानी होगी और बिचौलियों की भूमिका कम होगी।

ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़ा फैसला लिया गया है। कानपुर के घाटमपुर में 660 मेगावॉट की तीन इकाइयों वाले पावर प्लांट से बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इसकी दो इकाइयां पहले ही शुरू हो चुकी हैं और तीसरी जल्द शुरू होगी। इससे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी और दरों में लगभग 80 पैसे प्रति यूनिट तक कमी आने की संभावना है।

इसके साथ ही गोरखपुर को 'सोलर सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। चिलुआताल में 20 मेगावॉट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया जाएगा, जिसके लिए 80 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यह परियोजना न केवल बिजली उत्पादन बढ़ाएगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को आगे ले जाएगी। नवयुग पालिका योजना के तहत 1.50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 24 निकायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना उत्तर प्रदेश के शहरी विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इससे छोटे शहरों में भी निवेश के अवसर बढ़ेंगे और बड़े शहरों पर जनसंख्या का दबाव कम होगा। साथ ही, डिजिटल और तकनीकी विकास से प्रशासन अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।

हालांकि, इस योजना की सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। यदि परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं और गुणवत्ता बनाए रखी जाती है, तो यह पहल प्रदेश के शहरी ढांचे को पूरी तरह बदल सकती है।

कुल मिलाकर, योगी कैबिनेट के ये फैसले उत्तर प्रदेश के विकास को नई दिशा देने वाले हैं। नवयुग पालिका योजना, किसानों के लिए बढ़ा हुआ MSP, सस्ती बिजली और सोलर सिटी जैसे कदम यह दिखाते हैं कि सरकार शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के संतुलित विकास पर ध्यान दे रही है। आने वाले वर्षों में इन योजनाओं का प्रभाव प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष नागरिकों की शिकायतों और समस्याओं के ऑनलाइन निवारण का मार्च महीने का राज्य स्तरीय 'स्वागत' बुधवार, 25 मार्च को आयोजित होगा

गुरुवार, 26 मार्च को राम नवमी के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' बुधवार को होगा

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की उपस्थिति में हर महीने आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' (स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रिवेंसेस बाई एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी) कार्यक्रम बुधवार, 25 मार्च को आयोजित होगा।

ज्ञात हो कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से वर्ष 2003 से शुरू हुआ स्वागत ऑनलाइन जनशिकायत निवारण कार्यक्रम के तहत हर महीने के चौथे गुरुवार को राज्य स्तरीय स्वागत का आयोजन किया जाता है।

मार्च महीने के चौथे गुरुवार, 26 मार्च को राम नवमी के सार्वजनिक अवकाश को ध्यान में रखते हुए मार्च-2026 का राज्य स्तरीय 'स्वागत' कार्यक्रम इस बार बुधवार, 25 मार्च को आयोजित करने का निर्णय किया गया है।

इस 'स्वागत' कार्यक्रम के लिए नागरिक अपने अभ्यावेदन बुधवार, 25 मार्च की सुबह 8:00 से 11:00 बजे के दौरान मुख्यमंत्री की जनसंपर्क इकाई, स्वर्णिम संकुल-2, गांधीनगर में व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं।

मुख्यमंत्री दोपहर बाद इस राज्य स्तरीय 'स्वागत' में स्वयं उपस्थित रहकर नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे।

वैश्विक तनाव की आंधी में धड़ाम हुआ बाजार, सेंसेक्स 1800 अंक से ज्यादा टूटा

मुंबई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली, जिसने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें, विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी और रुपये की ऐतिहासिक कमजोरी ने मिलकर बाजार को गहरे लाल निशान में धकेल दिया। दिनभर के उतार-चढ़ाव के बाद BSE Sensex 1,836.57 अंक यानी 2.46 प्रतिशत गिरकर 72,696.39 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 50 601.85 अंक यानी 2.60 प्रतिशत टूटकर 22,512.65 के स्तर पर आ गया, जो 22,500 के अहम स्तर के नीचे का बंद है।

कारोबार के दौरान गिरावट और भी गहरी थी। सेंसेक्स लगभग 1,975 अंकों तक लुढ़क गया था, जो इस बात का संकेत है कि बाजार में घबराहट किस स्तर तक पहुंच चुकी है। निवेशकों ने जोखिम भरे एसेट्स से दूरी बनाते हुए सुरक्षित निवेश विकल्पों की ओर रुख किया, जिससे बिकवाली का दबाव और बढ़ गया।

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है। वैश्विक स्तर पर चल रहे संघर्ष ने ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ा दी है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़े जोखिमों ने निवेशकों को डरा दिया है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से की तेल आपूर्ति इसी मार्ग से गुजरती है। इसके चलते कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देश पर पड़ता है।

ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर 113.3 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जो पिछले कई महीनों का उच्चतम स्तर है। तेल की कीमतों में यह उछाल न केवल महंगाई को बढ़ाने का खतरा पैदा करता है, बल्कि कंपनियों के मुनाफे पर भी दबाव डालता है। यही कारण है कि निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफावसूली शुरू कर दी।

रुपये की कमजोरी ने बाजार की स्थिति को और खराब कर दिया। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 48 पैसे गिरकर 94.01 के नए सर्वकालिक निचले स्तर पर पहुंच गया। यह गिरावट इस बात का संकेत है कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से लगातार पैसा निकाल रहे हैं और डॉलर की मांग बढ़ रही है।

विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की लगातार बिकवाली भी बाजार के लिए बड़ा झटका साबित हुई है। आंकड़ों के अनुसार, केवल पिछले कारोबारी सत्र में ही एफआईआई ने 5,518 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 5,706 करोड़ रुपये की खरीदारी कर बाजार को कुछ हद तक संभालने की कोशिश की, लेकिन यह पर्याप्त नहीं रहा। इस महीने अब तक विदेशी निवेशक करीब 88,000 करोड़ रुपये से अधिक की निकासी कर चुके हैं, जो बाजार के लिए चिंता का बड़ा कारण है।

सेंसेक्स की कंपनियों पर नजर डालें तो ज्यादातर शेयरों में गिरावट देखने को मिली। टाइटन के शेयरों में सबसे ज्यादा 6.24 प्रतिशत की गिरावट आई। इसके अलावा ट्रेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा स्टील और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज शेयर भी दबाव में रहे। हालांकि, आईटी सेक्टर के कुछ शेयरों जैसे एचसीएल टेक, इंफोसिस और टेक महिंद्रा में मामूली बढ़त देखने को मिली, जिसने गिरावट को थोड़ा सीमित करने का प्रयास किया।

यह गिरावट केवल भारतीय बाजार तक सीमित नहीं रही। एशियाई बाजारों में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स 6.49 प्रतिशत तक गिर गया, जबकि जापान का निक्केई 225, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंग सेंग भी लाल निशान में बंद हुए। यूरोपीय बाजारों में भी इसी तरह का नकारात्मक रुख देखने को मिला, जो इस बात का संकेत है कि वैश्विक स्तर पर निवेशकों का भरोसा कमजोर पड़ा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्थिति में बाजार पर कई तरह के दबाव एक साथ काम कर रहे हैं। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के अनुसंधान प्रमुख विनोद नायर के अनुसार, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ऊर्जा आपूर्ति में संभावित व्यवधानों ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है।

क्रूड ऑयल वायदा 758 रुपये लुढ़काः सोना वायदा 1.29 लाख रुपये और चांदी वायदा 1.99 लाख रुपये तक गिरकर

मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 684471.19 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 94835.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 589635.46 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 9051.45 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 76141.94 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 140158 रुपये के भाव पर खूलकर, 140525 रुपये के दिन के उच्च और 129595 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 144492 रुपये के पिछले बंद के सामने 5443 रुपये या 3.77 फीसदी गिरकर 139049 रुपये प्रति 10 ग्राम हुआ। गोल्ड-गिनी मार्च वायदा 4863 रुपये या 4.11 फीसदी गिरकर 113317 रुपये प्रति 8 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-पेटल मार्च वायदा 610 रुपये या 4.12 फीसदी गिरकर 14194 रुपये प्रति 1 ग्राम के भाव पर पहुंचा। सोना-मिनी अप्रैल वायदा 140667 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140667 रुपये और नीचे में 129312 रुपये पर पहुंचकर, 5471 रुपये या 3.78 फीसदी गिरकर 139126 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-टेन मार्च वायदा प्रति 10 ग्राम 140726 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 140726 रुपये और नीचे में 129500 रुपये पर पहुंचकर, 145078 रुपये के पिछले बंद के सामने 5931 रुपये या 4.09 फीसदी गिरकर 139147 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा।

चांदी के वायदाओं में चांदी मई वायदा सत्र के आरंभ में 217702 रुपये के भाव पर खूलकर, 223449 रुपये के दिन के उच्च और 199643 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 226772 रुपये के पिछले बंद के सामने 5272 रुपये या 2.32 फीसदी की गिरावट के साथ 221500 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी अप्रैल वायदा 6276 रुपये या 2.71 फीसदी गिरकर 225472 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि चांदी-माइक्रो अप्रैल वायदा 6227 रुपये

▶▶ कमोडिटी वायदाओं में 94835.74 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 589635.46 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर : सोना-चांदी के वायदाओं में 76141.94 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार

या 2.68 फीसदी की गिरावट के साथ 225777 रुपये प्रति किलो के भाव पर कारोबार कर रहा था।

मेटल वर्ग में 7017.94 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा मार्च वायदा 8.1 रुपये या 0.73 फीसदी की तेजी के संग 1116.1 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता मार्च वायदा 2.45 रुपये या 0.8 फीसदी की मजबूती के साथ 310.1 रुपये प्रति किलो बोला गया। इसके सामने एल्यूमीनियम मार्च वायदा 2.1 रुपये या 0.63 फीसदी औंधकर 329.2 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा मार्च वायदा 75 पैसे या 0.4 फीसदी चढ़कर 188.6 रुपये प्रति किलो के भाव पर पहुंचा।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 10666.27 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल अप्रैल वायदा सत्र के आरंभ में 9283 रुपये के भाव पर खूलकर, 9620 रुपये के दिन के उच्च और 8431 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 758 रुपये या 8.19 फीसदी गिरकर 8500 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी अप्रैल वायदा 758 रुपये या 8.19 फीसदी की गिरावट के साथ 8501 रुपये प्रति बैरल के भाव पर कारोबार कर रहा था। इनके अलावा नैचुरल गैस मार्च वायदा सत्र के आरंभ में 288.8 रुपये के भाव पर खूलकर, 296.5 रुपये के दिन के उच्च और 278 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 288.1 रुपये के पिछले बंद के सामने 8.4 रुपये या 2.92 फीसदी की गिरावट के साथ 279.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर कारोबार कर रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी मार्च वायदा 8.4 रुपये या 2.91 फीसदी घटकर 279.8 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था।

कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल मार्च वायदा 992.9 रुपये पर खूलकर, 3.4 रुपये या 0.33 फीसदी औंधकर 1015 रुपये प्रति किलो पर आ गया। कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 54544.95 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 21596.99 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5917.87 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 545.59 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 14.35 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 534.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 8251.22 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 2394.74 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 15.65 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 1.64 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 9114 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 59209 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 28980 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 362962 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 65052 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 7056 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 19853 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 76174 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 22929 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 25399 लोट के स्तर पर था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल अप्रैल 10000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 234.1 रुपये की गिरावट के साथ 404.1 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 4.85 रुपये की गिरावट के साथ 3.85 रुपये हुआ।

सोना मार्च 140000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 2928.5 रुपये की गिरावट के साथ 2600 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 250000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 511 रुपये की बढ़त के साथ 1750.5 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1150 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 17 पैसे की नरमी के साथ 3.55 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 330 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 19 पैसे के सुधार के साथ 1.62 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल अप्रैल 7000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 125.3 रुपये की बढ़त के साथ 268.2 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस मार्च 290 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 6.1 रुपये की बढ़त के साथ 16.65 रुपये हुआ।

सोना मार्च 120000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 77.5 रुपये की बढ़त के साथ 128 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी मार्च 200000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 619.5 रुपये की बढ़त के साथ 2235 रुपये हुआ। तांबा मार्च 1080 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 3.76 रुपये की गिरावट के साथ 3.06 रुपये हुआ। जस्ता अप्रैल 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 1.66 रुपये की बढ़त के साथ 6.45 रुपये हुआ।

विश्व टीबी दिवस: पीएम मोदी के ‘टीबी मुक्त भारत’ विजन का चैंपियन बना गुजरात, 92% इलाज सफलता दर के साथ राष्ट्रीय उन्मूलन अभियान में सबसे आगे

- **94% लक्ष्य हासिल: नीति आयोग के 1.40 लाख के लक्ष्य के मुकाबले 1,31,801 टीबी मरीजों की सफलतापूर्वक पहचान कर किया पंजीकरण**
- **49.10 करोड़ की वित्तीय सहायता: निरंतर पोषण सहायता सुनिश्चित करने के लिए 2025 में 92,921 मरीजों को दी गई प्रत्यक्ष वित्तीय मदद**
- **4.49 लाख पोषण किट: 31,058 पंजीकृत सामुदायिक स्वयंसेवकों (निक्षय मित्रों) के मजबूत नेटवर्क के माध्यम से मरीजों को वितरित की गई पोषण किट**
- **75.39 लाख लोगों की स्क्रीनिंग: सघन टीबी उन्मूलन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर सक्रिय परीक्षण किया गया, जिससे 1.63 लाख नए मामलों को सक्रिय देखभाल के दायरे में मिली सफलता**

गांधीनगर : गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘टीबी मुक्त भारत’ के विजन को तेजी से साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में, राज्य ने नीति आयोग द्वारा निर्धारित टीबी पंजीकरण और उपचार के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का 94% हासिल कर लिया है, जिससे इस बीमारी के उन्मूलन में एक राष्ट्रीय अग्रणी के रूप में राज्य की स्थिति मजबूत हुई है। इस स्वास्थ्य सफलता का पैमाना विश्व टीबी दिवस पर गुजरात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा क्लिनिकल आंकड़ों में विस्तार से बताया गया है। वर्ष 2025 में 1,40,000 टीबी मामलों की पहचान करने के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य के मुकाबले, राज्य ने सफलतापूर्वक 1,31,801 मरीजों की पहचान की और उनका पंजीकरण किया। लेकिन यह प्रयास सिर्फ पहचान करने

तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि इसे अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया गया। पहचाने गए मरीजों में से 1,25,301 मरीजों को तुरंत सक्रिय उपचार के दायरे में लाया गया। निरंतर मेडिकल फॉलो-अप की बदौलत, 1,21,912 मरीजों ने अपना इलाज पूरी तरह से संपन्न किया, जिससे 91.74% की अत्यधिक सराहनीय क्लिनिकल रिकवरी दर हासिल हुई।

वित्तीय और पोषण सहायता से लड़ाई को मिली ताकत

यह मानते हुए कि टीबी के खिलाफ लड़ाई सिर्फ क्लीनिकों में नहीं बल्कि घरों में भी लड़ी जाती है, राज्य सरकार ने मरीजों के वित्तीय बोझ को काफी कम किया है। लंबे समय तक चलने वाला इलाज अक्सर आर्थिक कठिनाइयां लाता है, जिसके कारण कई बार मरीज बीच में ही इलाज छोड़ देते हैं। इससे निपटने के लिए, गुजरात सरकार ने अकेले 2025 में 92,921 टीबी मरीजों को 49.10 करोड़ की राशि वितरित की। निक्षय पोषण योजना के तहत, मरीजों को हर महीने 1,000 की महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य इलाज के दौरान उनके पोषण स्तर को बनाए रखना है।

इस वित्तीय मदद को अभूतपूर्व सामुदायिक समर्थन से और मजबूती मिली है। प्रधानमंत्री के ‘टीबी मुक्त भारत अभियान’ से प्रेरित होकर, गुजरात ने राष्ट्रीय पोर्टल पर 31,058 निक्षय मित्रों (सामुदायिक स्वयंसेवकों और प्रायोजकों) को पंजीकृत करके स्वास्थ्य सहायता को सफलतापूर्वक जन-भागीदारी से जोड़ा है। 10,682 सक्रिय स्वयंसेवकों के प्रयासों से इन निक्षय मित्रों ने मरीजों को 4.49 लाख से अधिक पोषण किट वितरित की हैं, जो समुदाय-संचालित पोषण सहायता में गुजरात को देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बनाता है।

प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग का महाभियान: 75.39 लाख लोगों की जांच, 1.63 लाख नए मरीजों की पहचान

दिसंबर 2024 में शुरू किए गए भारत सरकार के “100-दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान” का नेतृत्व करते हुए, राज्य ने बड़े पैमाने पर घर-घर जाकर सामुदायिक स्क्रीनिंग का काम किया। 20 मार्च 2026 तक, अविश्वसनीय रूप से 75.39 लाख लोगों की टीबी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इस सक्रिय अभियान ने सफलतापूर्वक 1,63,426 नए मरीजों की पहचान की है।

इतना ही नहीं, बीमारी के गंभीर होने या उनके समुदाय में फैलने से पहले ही उन्हें राज्य के मजबूत उपचार तंत्र में निर्बाध रूप से शामिल कर लिया गया है। नैदानिक दक्षता, वित्तीय सुरक्षा, सामुदायिक लामबंदी और सक्रिय प्रारंभिक पहचान के एक शक्तिशाली संयोजन के माध्यम से, गुजरात सिर्फ टीबी का इलाज ही नहीं कर रहा है, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए एक स्पष्ट और अनुकरणीय रास्ता भी तैयार कर रहा है।

मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में वातानुकूलित कोचों की स्थायी वृद्धि, यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त सुविधा

यात्रियों की सुविधा एवं रेलवे बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक मेल/एक्सप्रेस ट्रेन में न्यूनतम 06 स्लीपर श्रेणी कोच उपलब्ध कराने तथा वातानुकूलित कोचों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल से होकर चलने वाली मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों की संरचना में स्थायी रूप से वातानुकूलित श्रेणी कोचों की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस निर्णय से वातानुकूलित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त स्थान उपलब्ध होगा तथा भीड़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी के अनुसार संशोधित कोच संरचना का विवरण निम्नानुसार है —

1. गाड़ी संख्या 19217/19218 बान्द्रा टर्मिनस-वेरावल एक्सप्रेस संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच बान्द्रा टर्मिनस से 22 मई, 2026 से तथा वेरावल से 23 मई 2026 से प्रभावी होंगे।
2. गाड़ी संख्या 12971/12972 बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर के ट्रेन संरचना में संशोधन कर थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 की जाएगी। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 21 मई, 2026 से तथा बान्द्रा टर्मिनस से 24 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।
3. गाड़ी संख्या 19271/19272 भावनगर-हरिद्वार एक्सप्रेस में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 21 मई, 2026 से तथा हरिद्वार से 23 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।
4. गाड़ी संख्या 12941/12942 भावनगर-आसनसोल सुपरफास्ट में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 26 मई, 2026 से तथा आसनसोल से 28 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।
5. गाड़ी संख्या 22963/22964 बान्द्रा टर्मिनस-भावनगर सुपरफास्ट में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच भावनगर टर्मिनस से 24 मई, 2026 से तथा बान्द्रा टर्मिनस से 25 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।
6. गाड़ी संख्या 19319/19320 वेरावल-इंदौर एक्सप्रेस में संशोधित संरचना के अनुसार थर्ड एसी श्रेणी कोचों की संख्या 6 से बढ़ाकर 7 किए जाएंगे। ये कोच इंदौर से 26 मई, 2026 से तथा वेरावल से 27 मई, 2026 से प्रभावी होंगे।

उदयपुर पुलिस मीराबाई के बेटे की शादी में शामिल हुई और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए 1,11,000 रुपये का उपहार दिया

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। पुलिसकर्मी भी आम इंसान होते हैं। वे भी आम लोगों की तरह भावनाएं, प्रेम, करुणा, दया, क्रोध आदि व्यक्त करते हैं। लेकिन यहां एक ऐसी महिला की भावुकता, प्रेम, करुणा और आत्मसम्मान की कहानी है जो जानने योग्य है। बात यह है कि उदयपुर के प्रताप नगर पुलिस स्टेशन में, 25 वर्षों से पुलिस स्टेशन में खाना बनाने वाली मीराबाई के बेटे के लिए पुलिसकर्मियों ने मामा बनकर जिम्मेदारी संभाली। रविवार शाम को, पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष पूरनसिंह राजपुरोहित समेत सभी पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़े बजाते हुए मीराबाई के घर पहुंचे। उस समय उन्होंने पारंपरिक ढंग से सजाई हुई थाली में ममेरू लेकर प्रवेश किया। सजी हुई थाली में कपड़े और नकदी लेकर पुलिसकर्मी मंडप पहुंचे और वर्दी के ऊपर सिर पर सफा बांधा। मीराबाई ने पुलिसकर्मियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। और जब पुलिस दल ने उन्हें प्रशंसा के प्रतीक के रूप में 1,11,000 रुपये नकद से भरी थाली भेंट की, तो मीराबाई भावुक हो गईं।

मीराबाई पिछले 25 वर्षों से पुलिस स्टेशन में रसोइया के रूप में काम कर रही हैं। और वह सभी पुलिसकर्मियों की माँ की तरह देखभाल करती हैं। उनके इस स्नेह को देखकर पुलिस स्टेशन के कर्मचारियों ने मिलकर फैसला किया कि अगर पुलिसकर्मियों द्वारा उनके बेटे की शादी में मामेरू (शादी की रस्म) निभाई जाए, तो यह समाज में एक अलग मिसाल कायम करेगा। मीराबाई बताती हैं कि जब उनका बेटा मुकेश छह महीने का था, तब उनके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उन्होंने अकेले ही कड़ी मेहनत करके अपने बेटे का पालन-पोषण किया है। इस प्रकार, यह मामला पुलिस के दूसरे पहलू का एक जीवंत उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जो पुलिस को उजागर करने के साथ-साथ पुलिसकर्मियों को भी मानवीय रूप में प्रस्तुत करता है।

ईरान-अमेरिका-इजराइल युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला दिया, कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति बाधित कर दी, भारत भी इससे प्रभावित हुआ

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ अमेरिका और इज़राइल के बीच छिड़ा संघर्ष पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। मिसाइलों और घातक बमों के व्यापक इस्तेमाल से इस संघर्ष की तीव्रता स्पष्ट है। क्रूरता इस हद तक पहुंच गई है कि युद्ध कानूनों का उल्लंघन करते हुए नागरिक क्षेत्रों पर बम गिराए जा रहे हैं। शिक्षण संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। विशेष रूप से, ईरान में एक लड़कियों के स्कूल पर बमबारी की गई, जिसमें कई छात्राओं की मौत हो गई। और यह युद्ध ईरान पर थोपा गया था। जिसका परिणाम आज पूरी दुनिया के सामने है, फिर भी कोई भी देश अमेरिका या इज़राइल से इस बारे में सवाल करने का साहस नहीं रखता। पश्चिम एशिया में जारी भीषण युद्ध के बीच, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह चिंता बढ़ रही है कि यदि स्थिति बिगड़ती रही तो आने वाले दिनों में संकट और अधिक व्यापक और गंभीर हो सकता है। वास्तविकता यह है कि इज़राइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर संयुक्त हमले के बाद युद्ध जिस दिशा में आगे बढ़ा है, उससे शांति की संभावनाएं धूमिल होती जा रही हैं। एक ओर, बीएसई सूचकांक लगभग 2500 अंक गिर गया, वहीं एनएसई निफ्टी 775 अंक गिर गया। जून 2024 के बाद इन सूचकांकों में एक दिन में दर्ज की गई यह सबसे बड़ी गिरावट है। हालांकि, इस तरह की बाजार गिरावट अक्सर विभिन्न कारकों के एक साथ आने का परिणाम होती है। इस मामले में, वैश्विक स्तर पर मूल कारण स्पष्ट है और वह यह है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि, साथ ही पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचनाओं और तेल एवं गैस सुविधाओं पर हमलों में तेजी आना, इस बाजार में आई गिरावट का मुख्य कारण है। इसका निवेशकों के विश्वास पर स्वाभाविक रूप से बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जिसके कारण मौजूदा उथल-पुथल को लेकर असुरक्षा की भावना फैल गई है। दरअसल, जब से ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अवरुद्ध किया है, वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बाधित हो गई है। भारत समेत कई देश इस स्थिति से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और अब तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोतों की तलाश में जुटे हैं। इसी संदर्भ में भारत ने रूस से तेल की खरीद बढ़ा दी है। यह आशंका भी है कि भारत की प्राकृतिक गैस आपूर्ति गंभीर रूप से बाधित हो सकती है। कतर के रास लाफान पर हुए हमले के बाद यह आशंका निराधार नहीं है। अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर संयुक्त हमला कर दिया है, लेकिन जिस तरह से तीनों देश नुकसान झेल रहे हैं, अगर यह युद्ध लंबा चलता है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि भारत को लकड़ी और कोयले का सहारा भी लेना पड़ेगा । अंततः, समझौता ही एकमात्र बड़ा हथियार है। लेकिन इसकी व्याख्या कौन कर सकता है?

आय और जाति प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड में नाम जोड़ने-हटाने जैसी 20 सेवाएं अब उंगलियों पर उपलब्ध

- **‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पहल के जरिए उन 20 सेवाओं का सरलीकरण, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन आते हैं**
- **मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सरकार नागरिकों के द्वार तक पहुंच रही है, उन 20 सेवाओं को नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए अब ऑनलाइन किया जा रहा है, जिनके लिए सबसे अधिक आवेदन मिलते हैं**
- **प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को साकार कर रही है गुजरात सरकार, सरकारी सेवाओं के केंद्र में है नागरिक-केंद्रित प्रशासन**

गांधीनगर : गुजरात प्रशासनिक सुधार आयोग (जीएआरसी) की पांचवीं रिपोर्ट की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर सरकार ने विभिन्न विभागों की ऐसी 20 सेवाओं को ऑनलाइन किया है, जिनके लिए सबसे आवेदन प्राप्त होते हैं।

जीएआरसी की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के अंतर्गत उपलब्ध सेवाओं में से लगभग 4 फीसदी सेवाओं के लिए संपूर्ण एंड-टू-एंड डिजिटल डिलीवरी को पहले से ही सक्रिय कर दिया गया है। वर्तमान में जन सेवा केंद्रों और ई-ग्राम केंद्रों के मार्फत बड़ी संख्या में सेवाएं सफलतापूर्वक प्रदान की जा रही हैं, जो राज्य की मजबूत सेवा वितरण व्यवस्था और व्यापक उपलब्धता को दर्शाती है तथा डिजिटल पहुंच को और अधिक विस्तार देने के विशाल अवसर भी प्रदान करती है।

डिजिटल गुजरात प्लेटफॉर्म के तहत प्रतिवर्ष लगभग 1.20 करोड़ आवेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें से लगभग 87 लाख आवेदन इन 20 उच्च-ट्रांजेक्शन सवाओं के लिए मिलते हैं, जो नागरिक जीवन में इन सेवाओं के महत्व को दर्शाता है।

इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ‘सुगम डिजिटल गुजरात’ पहल क्रियान्वित की जा रही है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य फेसलेस, कैशलेस और पेपरलेस

प्रशासन को बढ़ावा देकर सरकारी सेवाओं को अधिक आसान, तेज और पारदर्शी बनाना है, ताकि नागरिकों को ये सेवाएं आसानी से और उंगलियों पर उपलब्ध हो सकें।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन को गुजरात सरकार साकार कर रही है। सरकार की सेवाओं के केंद्र में ‘नागरिक-केंद्रित प्रशासन’ का दृष्टिकोण है।

इस अभियान के पहले चरण में 20 ऐसी सेवाओं को शामिल किया गया है, जिनके लिए सर्वाधिक आवेदन मिलते हैं। इन सेवाओं में, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी), राजस्व विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एफसीएस), विधि विभाग और आदिजाति विकास विभाग शामिल हैं। नागरिक राज्य सरकार के डिजिटल गुजरात पोर्टल के जरिए इन सेवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इन सेवाओं में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की 11 सेवाएं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की 6 सेवाएं, राजस्व विभाग, विधि विभाग और आदिजाति विकास विभाग की 1-1 सेवा शामिल है।

इन विभागों की सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी

- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (एसजेईडी) : एसईबीसी (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग) प्रमाण पत्र (ग्रामीण/शहरी), नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट (गुजरात और भारत सरकार), ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र।
- खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (एफसीएस) : राशन कार्ड में नाम जोड़ना या हटाना, सुधार करना, अलग राशन कार्ड, नया राशन कार्ड और डुप्लीकेट राशन कार्ड।
- राजस्व विभाग : प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए अनुरोध।
- विधि विभाग : अन्य तैयार शपथ पत्र।
- आदिजाति विकास विभाग : अनुसूचित जनजाति (एसटी) जाति प्रमाण पत्र।

डिजिटल गुजरात के तहत इन पांच विभागों की 20 नागरिक-उन्मुख सेवाओं के लिए सबसे अधिक आवेदन मिलते हैं। इन सेवाओं को ऑनलाइन करने से नागरिकों के डेटा की एक बार एंट्री करने के बाद उसे विभिन्न सेवाओं में दोबारा उपयोग में लिया जा सकता है। इसके अलावा, अनावश्यक दस्तावेजों की मांग को खत्म कर आवेदन फॉर्म को काफी आसान बनाया गया है। इसके अलावा, दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन किया जाएगा। आधार कार्ड-आधारित पहचान, एपीआई द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड जांच और डिजिलॉकर एकीकरण किया जाएगा।

खास बात यह है कि इन 20 सेवाओं का लाभ उठाने के लिए ई-साइन सुविधा, वॉट्सऐप के जरिए सेवा वितरण, क्यूआर कोड-सक्षम प्रमाण पत्र और यूपीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जैसी व्यवस्था की गई है।

सरकार की भविष्य की योजना आगामी समय में ऐसी और सेवाओं को सुगम डिजिटल गुजरात पहल के तहत शामिल करने और गुजराती भाषा का एआई मॉडल्स बनाने जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी-आधारित प्रोजेक्ट शुरू करने की है।

सुधारों से पड़ेगा सकारात्मक प्रभाव, नागरिकों को मिलेगी राहत

- तेज सेवा वितरण : जीपीआर (गवर्नमेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग) के कारण प्रशासनिक स्तर पर अनुमति के चरण कम हो जाएंगे, जिससे आवेदन का निस्तारण समय घट जाएगा।
- पारदर्शिता आएगी : सेवाएं ‘फेसलेस’ बनने से ऑनलाइन पोर्टल के जरिए नागरिकों को पारदर्शी सेवाएं मिलेंगी।
- धन और समय की बचत : नागरिकों को दफ्तर तक जाने की जरूरत नहीं होगी (प्रेसेंस-लेस)। इससे परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।
- सटीक डेटा : एपीआई और एप्लीकेशन डेटा के एकीकरण के कारण सरकारी डेटा की विश्वसनीयता बढ़ेगी और प्रमाण पत्रों में होने वाली त्रुटियां न्यूनतम हो जाएंगी।

मुआवजे की रकम पर डाका: 5 लाख की घूस लेते रंगे हाथ दबोचे गए बड़ा बाबू और दलाल

सरायकेला। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सरायकेला-खरसावां जिला समाहरणालय से जुड़े भू-अर्जन विभाग के एक बड़े बाबू और उसके कथित दलाल को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। पांच लाख रुपये की घूस लेते हुए पकड़े गए इन दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आम जनता को अपने ही अधिकारों के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

जानकारी के अनुसार, भू-अर्जन विभाग में तैनात बड़ा बाबू प्रीतम कुमार आचार्य और दलाल विनय कुमार तिवारी को एसीबी की टीम ने सुनियोजित जाल बिछाकर गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई चांडिल के धुनाबुरू गांव निवासी गुरुचरण सिंह सरदार की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मुआवजे की राशि दिलाने के नाम पर भारी रिश्वत की मांग की जा रही है।

दरअसल, धुनाबुरू गांव में पावर ग्रिड परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया था, जिसके एवज में गुरुचरण सिंह सरदार को करीब डेढ़ करोड़ रुपये का मुआवजा मिलना था। लेकिन इस मुआवजे को जारी करने के लिए संबंधित अधिकारी ने कथित तौर पर पहले 60 लाख रुपये की घूस मांगी। बाद में यह रकम 40 लाख रुपये पर तय हुई। यह अपने आप में इस बात का संकेत है कि किस तरह भ्रष्टाचार का जाल सरकारी दफ्तरों में गहराई तक फैला हुआ है, जहां अधिकारी खुलेआम सौदेबाजी करते हैं।

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस सौदे के तहत दो चेक, प्रत्येक 20-20 लाख रुपये के, दलाल को दिए गए थे। यह तय हुआ था कि जैसे ही नकद रकम का भुगतान होगा, चेक वापस कर दिए जाएंगे। इसी प्रक्रिया के तहत सोमवार को पांच लाख रुपये की पहली किस्त दी जानी थी, जिस पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दलाल को रंगे हाथ पकड़ लिया।

एसीबी की टीम ने इस पूरे ऑपरेशन को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया। जैसे ही दलाल विनय कुमार तिवारी ने घूस की रकम ली, उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद टीम ने उससे पूछताछ की और उसके मोबाइल फोन के जरिए बड़ा बाबू प्रीतम कुमार आचार्य को समाहरणालय के बाहर बुलाया गया। जैसे ही प्रीतम मौके पर पहुंचा, एसीबी की टीम ने उसे भी दबोच लिया।

भावनगर मंडल के 04 कर्मचारी डीआरएम संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल में सुरक्षित रेल परिचालन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले चार कर्मचारियों को आज मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा डीआरएम संरक्षा पुरस्कार (DRM Safety Award) से सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, भावनगर परा में आयोजित किया गया।

सम्मानित कर्मचारियों में श्री कन्हैयालाल कनाडा (प्वाइंट्समैन–धोलका), श्री घनश्याम सी. (प्वाइंट्समैन –लाठीदड स्टेशन), श्री सतीश जी. (प्वाइंट्समैन –बोटाद जंक्शन) तथा श्री सत्यजीत पाण्डेय (प्वाइंट्समैन–अलमपर स्टेशन) शामिल हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी सतर्कता, सूझबूझ एवं त्वरित कार्रवाई से संभावित दुर्घटनाओं को टालते हुए रेल संरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की सराहना करते हुए उन्हें अन्य कर्मचारियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की उच्च स्तर की प्रतिबद्धता एवं कर्तव्यनिष्ठा सुरक्षित रेल संचालन की आधारशिला है।

घटनाओं का संक्षिप्त विवरण:

श्री कन्हैयालाल कनाडा ने 10 मार्च 2026 को गाड़ी संख्या 20965 गांधीग्राम–भावनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसएलआर से धुआँ निकलते देखा। उन्होंने तत्काल ट्रेन मैनेजर एवं स्टेशन मास्टर को सूचित किया, जिसके फलस्वरूप धोलका स्टेशन पर संबंधित कोच को अलग कर संभावित दुर्घटना को टाल दिया गया।

श्री घनश्याम सी. ने 20 नवंबर 2025 को लाठीदड स्टेशन पर एक मालगाड़ी के सातवें एवं आठवें वैगन में हॉट एक्सल की गंभीर स्थिति देखी। उन्होंने तुरंत स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिसके बाद ट्रेन को रोका गया और आवश्यक सुधार कर सुरक्षित रवाना किया गया।

श्री सतीश जी. ने 12 नवंबर 2025 को बोटाद जंक्शन पर एक मालगाड़ी में हैंगिंग पार्ट देखा। उन्होंने तत्परता से लोको पायलट को खतरे का संकेत देकर ट्रेन रुकवाई तथा लटके हुए पार्ट को सुरक्षित कर ट्रेन को आगे बढ़ाया गया।

श्री सत्यजीत पाण्डेय ने 16 नवंबर 2025 को अलमपर स्टेशन पर एक मालगाड़ी के दो वैगनों में चिंगारी देखी। उन्होंने तुरंत डेंजर सिग्नल देकर ट्रेन रुकवाई, जांच में ब्रेक जाम पाया गया, जिसे ठीक कर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित किया गया।

मंडल रेल प्रबंधक ने सभी सम्मानित कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार उत्कृष्ट कार्य करते रहने हेतु प्रोत्साहित किया।

पश्चिम रेलवे का भावनगर मंडल अपने कर्मचारियों की त्वरित सोच, साहस एवं सतर्कता की सराहना करता है, जिनके प्रयासों से न केवल रेल संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हुई, बल्कि संभावित दुर्घटनाओं को भी प्रभावी रूप से रोका जा सका।

अहमदाबाद में वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों के साथ “संवाद” कार्यक्रम आयोजित,यात्री सेवाओं एवं राजस्व वृद्धि पर विशेष जोर

पश्चिम रेलवे के वाणिज्य विभाग में कार्यरत रेल कर्मचारियों के साथ “संवाद” कार्यक्रम का आयोजन आज अहमदाबाद मंडल में किया गया। यह संवाद सत्र श्री तरुण जैन, प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, पश्चिम रेलवे एवं श्री वेद प्रकाश, मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद के नेतृत्व में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य वाणिज्य प्रबंधक (यात्री विपणन) एवं मुख्य दावा अधिकारी, पश्चिम रेलवे श्री जगदीश प्रसाद, अपर मण्डल रेल प्रबंधक, अहमदाबाद श्रीमती मंजु मीना, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, अहमदाबाद श्री अन्नू त्यागी सहित वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे।

इसके अतिरिक्त, पश्चिम रेलवे के सभी मंडलों से वाणिज्य विभाग के कर्मचारी भी इस संवाद कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल हुए, जिससे यह सत्र व्यापक प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मुख्यालय स्तर के नेतृत्व एवं मंडल स्तर के कर्मचारियों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना तथा यात्री विपणन (Passenger Marketing), बुकिंग, आरक्षण एवं कैटरिंग से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करना था। साथ ही, इस सत्र में फील्ड स्तर पर आने वाली चुनौतियों एवं नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

रेल कर्मचारियों के साथ “संवाद”

- रेल कर्मचारियों (जैसे बुकिंग क्लर्क, रिजर्वेशन क्लर्क, कमर्शियल सुपरवाइजर, कमर्शियल इंस्पेक्टर, टिकट चेकिंग स्टाफ, कैटरिंग स्टाफ एवं अन्य वाणिज्य विभाग के कर्मचारी) को अपनी समस्याओं, सुझावों एवं अनुभवों को सीधे उच्च अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर प्राप्त हुआ।
- फील्ड स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों पर चर्चा की गई तथा उनके समाधान हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
- यात्री सेवाओं में सुधार, कार्यकुशलता बढ़ाने एवं बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया गया।
- संवाद के दौरान यात्रियों को उपलब्ध कराई जाने वाली मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल व्यवस्था, खानपान की गुणवत्ता, लिनेन की उपलब्धता एवं स्वच्छता से संबंधित मुद्दों पर भी विस्तृत चर्चा की गई तथा सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए।
- कर्मचारियों को नीतियों एवं नई पहलों की जानकारी देकर उनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रेरित किया गया।
- संवाद के माध्यम से प्रशासन एवं कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता एवं विश्वास को और सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।

प्रमुख उपलब्धियां

पश्चिम रेलवे द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में 20 मार्च 2026 तक कुल 8218.91 करोड़ का ओरिजनेटिंग यात्री राजस्व अर्जित किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.38% अधिक है। इसी अवधि में ओरिजनेटिंग यात्रियों की संख्या 1327.30 मिलियन दर्ज की गई।

अहमदाबाद मंडल ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 20 मार्च 2026 तक 1755.94 करोड़ का यात्री राजस्व अर्जित किया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.94% अधिक है। साथ ही, इस अवधि में 39.14 मिलियन यात्रियों को सेवाएं प्रदान की गईं।

राजस्व वृद्धि हेतु किए गए प्रमुख प्रयास

- यात्रियों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा विभिन्न पहल की गईं, जिनमें प्रमुख रूप से:
- 20 मार्च 2026 तक 4,621 विशेष ट्रेन यात्राओं का संचालन किया गया, जिससे लगभग 482.57 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ तथा लगभग 49.01 लाख यात्रियों को सुविधा प्रदान की गई।
- फरवरी 2026 तक 24 जोड़ी ट्रेनों में स्थायी रूप से 58 कोचों का विस्तार किया गया।
- अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने हेतु कुल 12,674 कोचों का संवर्धन (augmentation) किया गया, जिससे 86.64 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ।
- चालू वित्तीय वर्ष में 7 नई ट्रेनों की शुरुआत की गई।

यात्री सुविधा हेतु डिजिटल पहल

- यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मुंबई मंडल द्वारा “सरल रिफंड सेवा” (SARAL Refund Sewa) नामक डिजिटल पहल शुरू की गई है।
- इस सेवा के माध्यम से असफल डिजिटल लेनदेन पर रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब यात्री टिकट काउंटर पर उपलब्ध QR कोड स्कैन कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं।
- “संवाद” कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों को अपने विचार एवं सुझाव सीधे उच्चाधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिला। यह पहल न केवल कार्यकुशलता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि यात्री सेवाओं में और अधिक सुधार लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।